अब नीतीश के पूर्णिया में शेल्टर होम का भंडाफोड़, होटलों में भेजी जाती हैं लड़कियां

चरण सिंह राजपूत

नई दिल्ली/ पटना। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड से शर्मशार हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक और बुरी खबर है। सरकार जहां बिहार के विभिन्न शेल्टर होम की व्यरवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रही है वहीं एक ताजा मामला पूर्णिया के शेल्टर होम का सामने आया है। वहां से भागी एक लड़की ने आरोप लगाया है कि शेल्टर होम की लड़कियों को हवश का शिकार बनाया जाता है। उन्हें होटलों में भेजकर उनसे धंधा कराया जाता है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र में बालिकाओं के लिए जो शेल्टर होम हैं। विभिन्न परेशानियों का सामना कर रहीं 6 लड़कियां सोमवार की सुबह मौका देखकर भाग निकलीं। सूचना मिलने पर पुलिस ने भागने वाली पांच लड़कियों को बरामद कर लिया। एक लड़की भागने में कामयाब हो गई। किसी तरह से वह लड़की कुछ मीडियाकर्मियों के संपर्क में आ गई। उसने उन्हें आपबीती सुनाई। इस पीड़िता ने शेल्टर होम के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि कुछ दिन पहले वह घर से भाग गई थी। इस मामले में उसके परिजनों ने एक युवक के खिलाफ उसे भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था।

तभी से पुलिस उस लड़की को तलाश कर रही थी। गत 16 फरवरी को वह लड़की खुद ही सहायक थाना जा पहुंची थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसके माता-पिता ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया है। पुलिस ने उसे 19 फरवरी को पूर्णिया शेल्टर होम भेज दिया था। लड़की ने वहां जाकर देखा कि लड़कियों से धंधा कराया जाता है। उसे नहीं पता था कि वहां उसके साथ हैवानियत की हद होगी। मामला पुलिस तक पहुंच गया। मीडियाकर्मियों के दबाव के चलते अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

आरएसएस के हरियाणा चीफ.....

पेज एक का शेष

कराने का इल्जाम है । ओमप्रकाश जिंदल अभी भी पंजाब में रह रहे हैं ।

इसी बीच पता चला है कि रोहतक से जुड़ा बीजेपी का एक बड़ा नेता भी कई शिकारों को जिंदल के पास भेजता रहा है। रोहतक के कई लोगों के करोड़ों रुपये जिंदल परिवार के पास फंसे हुए हैं । पर सरकार के निशाने पर आने से डर रहे ये लोग खुल कर सामने आने और जिंदल परिवार की पोल खोलने से कतरा रहे हैं ।

हरियाणा पुलिस का सुरक्षा कवच

लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि लोगों को ठगने वाले इस पारिवारिक गिरोह के चंगुल से लोगों को बचाने की बजाय हरियाणा पुलिस इन को बाकायदा सुरक्षा कवच दे रही है । पुलिस को मालूम है कि अदालत से भगौड़े घोषित कई अपराधी जिंदल परिवार की तीनों कोठियों में उनकी नजरों के सामने हैं, लेकिन वे बिना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इशारा मिले इनका बाल तक बांका करने के बारे में सोच भी नहीं सकते ।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

गतांक की चीर-फ़ाड़

जनता को गुमराह करते मोदी के झूठ

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 3-9 मार्च 2019 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। अरावली पर्वत श्रंखला हरियाणा के पांच ज़िलों गुड़गांव, मेवात, फ़रीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ तथा दिल्ली से होकर गुजरती है। पर्वत श्रंखला में मौजूद अनगिनत पेड़ बारिश और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के साथ ही राजस्थान से उठने वाली धूल भरी आंधियों को भी रोकते हैं तथा यह वन्य जीवों के लिये भी बड़ी आश्रय स्थली है। इसके अतिरिक्त यहां मौजूद झीलों के कारण इलाके का भू-जल स्तर भी बना रहता है। परंतु नेताओं व अफ़सरों के मिलीभगत के कारण इस वन क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य, खनन तथा पेड़ों की कटाई का कार्य चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 1990 के बाद अरावली क्षेत्र में बने मकानों को धराशायी करने का आदेश दिया था तो हरियाणा की खट्टर सरकार ने नेताओं, अफ़सरों और बिल्डरों की ज़मीन बचाने के लिये पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम 1900 को ही संशोधित कर दिया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश ज़ारी किया था, जिसकी 'बिल्डर लॉबी के लिये खट्टर सरकार ने अरावली का रास्ता साफ कर दिया था साफ़-संघी मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे का बुलडोजर चलाया' में खरी विवेचना की गई है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त एक्ट में संशोधन पर स्टे लगा दिया है और इस संशोधित बिल का बड़ा प्रतिरोध किया जा रहा है। अरावली के खत्म होने से प्रदूषण व पानी की ऐसी समस्या खड़ी होगी, जिसकी अभी खट्टर सरकार कल्पना नहीं कर रहा है। यहां बड़ी बड़ी इमारतें व व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ने से प्रकृति के अलावा वन्य जीवों को भी नुकसान होगा तथा रेगिस्तान की तरफ़ से आने वाली धूल भरी हवाएं फ़रीदाबाद को भी रेगिस्तान बना देंगी। इससे न केवल फ़रीदाबाद बल्कि पूरे एनसीआर के वातावरण पर भी बड़ा असर पड़ेगा और सभी प्रभावित होंगे।

लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सड़क मंत्री नीतिन गडकरी केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गूजर तथा हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल ने 15 अगस्त 2014 को मंझावली गांव में यमुना पुल का शिलान्यास करने की तर्ज पर दिल्ली के मीठापुर गांव में हाइवे का शिलान्यास करके क्षेत्र की जनता को एक बार फ़िर झांसा देने का प्रयास किया है, जिसका 'मंझावली यमुना पुल के बाद एक और तोहफे (सड़क) का झांसा दिया मंत्री गडकरी ने -2014 शिलान्यास की पुनरावृत्ति में मंत्री गूजर और गोयल आज भी तालिया ही बजा रहे हैं' में खुलासा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी व केन्द्रीय मंत्री गडकरी दोनों की कथनी व करनी में अंतर है। गडकरी ने मोदीजी के झूठे वायदों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वे वही वायदा करते हैं जो वे पूरा कर सकते हैं। लेकिन गडकरी के अपने झूठ का जीता जागता उदाहरण मंझावली का यमुना पुल है जिसे उन्होंने 15 अगस्त 2016 तक चालू कर देने का वायदा किया था, जबकि पुल के लिये बनने वाले कुल 48 पिलरों में से अभी तक केवल 3 पर ही काम चल रहा है। ताजातरीन शिलान्यास की गई सड़क को पूरा होने की कोई तय सीमा गडकरी ने भी नहीं बताई है।

सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 13 फ़रवरी को 16 राज्यों के करीब 11.8 लाख वनवासी परिवारों के वन भूमि पर कब्जे के दावों को खारिज करते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे 27 जुलाई 2019 से पहले ज़मीन खाली करवाएं। केन्द्र सरकार के निवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने वनवासियों को राहत देते हुए उनकी बेदखली के अपने ही आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। परंतु आदिवासी और वनवासी परिवारों को बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध देश भर में आदिवासी समूहों द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिये विरोध प्रदर्शन किये जा रहे हैं, जिनकी 'ज़मीन से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में सड़क पर उतरे हजारों आदिवासी-अंतत: सरकार को आगे आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को स्थगित किया' में समीक्षा की गई है। इन्हें बेदखली से बचाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि एक मानवीय पक्ष के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी इससे जुड़ी है और जंगलों के परंपरागत निवासी ही उनकी रक्षा करने में समर्थ हैं।

अशिक्षित वनवासियों से उनकी पहचान से जुड़े तथ्य व दस्तावेज मांगना अव्यवहारिक लगता है, जिसके लिये कानून में बदलाव करने की आवश्यकता है।

देश भर में 1.82 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनका कम से कम एक सदस्य हाथ से सीवर और गटर की सफ़ाई के काम में लगा है और हर पांच दिन में एक सफ़ाईकर्मी गटर की सफ़ाई करते हुए जान दे देता है। देश में 1.6 लाख महिलाएं अभी भी गंदगी उठाने के लिये मजबूर हैं। इनके लिये प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो पांच साल में एक भी शब्द बोला और ना इनकी सहायता व पुनर्वास के लिये कोई प्रयास किए। परंतु 24 फ़रवरी को प्रयागराज कुम्भ के मेले में गये मोदी जी ने संगम में डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना की और फ़िर एक कमरे में कुर्सियों पर बैठे पांच सफ़ाई कर्मियों के पैर धोए तथा उन्हें सम्मानित किया। इस पूरे कर्मकांड की वीडियो रिकार्डिंग भी की गई। मोदीजी की इस नौटंकी की असलियत का 'अपना दिमाग साफ़ करिए, हमारे पैर नहीं.... ये अपमान की पराकाष्ठा है' में पर्दाफ़ाश किया गया है।

पुलवामा हमले में सीआरपीएफ़ के 44 जवानों के शहीद होने, पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायु सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर हमला करने, पाकिस्तान द्वारा रात के अंधेरे में इसका जवाब देने, पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमान और हमारे मिग-21 के धराशायी होने तथा विग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तानी क्षेत्र में पकड़े जाने की घटनाओं के संदर्भ में 'चुनाव की सूली पर देश की प्रतिष्ठा' में प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का सटीक विश्लेषण किया गया है। इस पूरे प्रकरण का सूत्रधार अमरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प थे जो शुरू से लेकर आखिर तक पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। अमेरिका ने दावा किया है कि इस उपमहाद्वीप में तनाव को कम करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे स्पष्ट है मोदीजी व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों अमेरिका के हाथ की कठपुतली बनकर काम कर रहे थे।

लोकसभा चुनाव जीतने के लिये प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल की असफलताओं से जनता को गुमराह करने हेतु सरहद की शरण में चले गए हैं। और उन्होंने अंध-राष्ट्रवाद, आतंकवाद व पाकिस्तान को अहम मुद्दा बना लिया है। '2014 का मोदी ही बन गया है आज के मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन' में मोदी जी द्वारा उनके भ्रष्टाचार की चर्चाओं को अंध-राष्ट्रवाद की तूफ़ान से मोड़ देने के प्रयास को असफ़ल करने के लिये विपक्ष के एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने चुनाव में इसे भुनाने के लिये भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रणनीतिकारों ने अपने प्रवक्ताओं और टीवी चैनलों पर बहस में भाग लेने वाले नेताओं को निर्देश दिया है कि वे राफेल के मुद्दे को कोई महत्व न दें बल्कि बालाकोट में भारतीय वायु सेना के हमले को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि की तरह पेश करें।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उनके मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव रीना राय की मिलीभगत से देश के 32 राज्य संसाधन केन्द्रों को बंद कर दिया गया है जिससे भारत के लोगों को पढा-लिखा बनाने के लिये केन्द्र सरकार के कार्यक्रम 'साक्षर भारत' को गहरा धक्का लगा है, जिसका 'केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की धांधली ...केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बर्बाद कर रहा है साक्षर भारत कार्यक्रम को-आईएएस अफ़सर रीना राय उसके इस मिशन में शामिल' में उजागर किया गया है। गौरतलब है कि राज्य संसाधन केन्द्र साक्षरता कार्यक्रम की रीढ़ होते हैं, जिनके बिना इस कार्यक्रम के संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

प्रयागराज में संगम मे डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पांच सफ़ाई कर्मियों के पैर धोने पर 'इलैक्शन... ? तो मुमकिन है....।? टीवी चैनलों के एंकरों द्वारा उत्तेजित व आक्रामक शैली में रिपोर्टिंग पर पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों की संभावित प्रतिक्रिया पर 'कहीं वहां के चैनल ही हमला ना कर दें। बहुत उत्तेजित हैं।',

योग गुरू रामदेव व श्री श्री रविशंकर द्वारा व्यवसाय करने पर 'धर्म को धंधे में मिला दो तो बहुत फ़ायदे हैं, वो कैसे?? किसान 50 रुपये लीटर गांय का दूध नहीं बेच पाता है-वहां हम 90 रुपये लीटर गाय का मूत बेचते हैं', सेना द्वारा आतंकियों के नाम पर आम नागरिकों को मारने पर 'हमें कैसे पता चले कि तुम आतंकवादियों को मार रहे हो या भटके हुए शांतिप्रिय भोले भाले नागरिकों को ?-आप आगे खड़े हो जाएं श्रीमान और मुझे बताते रहें किसे उड़ा दूं और किसे बख्श दूं...' तथा मोदी सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया पर दबाव बनाकर रिजर्व फंड से 28000 करोड़ रुपये ले लेने पर '70 साल में पहली बार - आखिरकार मोदी सरकार ने आरबीआई से 28000 करोड़ रुपये ले ही लिया, अब चुनाव में फूंकी जाएगी आपकी-हमारी मेहनत' कार्टूनों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी, सरकार , रामदेव व श्री श्री रविशंकर पर उपयुक्त तंज कसा गया है।